पीएसीएल निवेशक 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए कर सकते हैं आवेदनः सेबी

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। पीएसीएल के निवेशक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने यह जानकारी दी। बाजार नियामक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया था। न्यायालय ने आदेश में पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कहा था। समिति ने पहले पीएसीएल के ऐसे निवेशकों से दावे के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिनका कंपनी पर 2,500 रुपये तक का बकाया था। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीएसीएल ने अवैध तरीके से लोगों से कृषि और रीयल एस्टेट कारोबार के नाम पर 60,000 करोड़ रुपये जुटाये थे। सेबी ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी करके कहा कि सत्यापन के बाद दावों के संबंध में रिफंड किया गया और यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब समिति ने उन सभी निवेशकों से दावा प्राप्त करने का फैसला किया है, जिनका पैसा पीएसीएल लिमिटेड पर बकाया है। नियामक ने कहा कि दावे के संबंध में निवेशक ईबीआईपीएसीएलरिफंड डॉट को डॉट इन' वेबसाइट पर जा सकते हैं।

बजट के प्रस्ताव चुनाव की दृष्टि से नहीं : गोयल

मुंबई, 09 फरवरी (ए)। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पर विपक्षी दलों की आलोचनाओं का जवाब देते हुए शुक्रवार को कहा कि बजट 2019-20 में की गयी घोषणाएं आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से नहीं की गई हैं। गोयल ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा, '' बजट चुनाव की दृष्टि से नहीं बनाया गया है, 100 चीजें करने के लिए होती हैं... जरूरी और अति-मुद्दों पर इंतजार नहीं किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बजट में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। इस कदम का बचाव करते हुए गोयल ने कहा कि बजट में छोटे किसानों को जो सहायता दी गई वो खैरात नहीं है बल्कि किसानों के प्रति सरकार का कर्तव्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य किसानों की जानकारियां दे रहे हैं, यहां के किसानों को प्रस्तावित योजना का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह अंतरिम बजट ''लेखानुदान नहीं बल्कि वोट के लिए लोखा-जोखा है।

एंजल निवेशकों के लिए बढ़ सकती है निवेश सीमा

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल निवेश पर टैक्स छूट देने के लिए सरकार ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। नव उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें एंजल निवेशकों समेत अन्य माध्यमों से अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक जुटाने के मामले में एंजल टैक्स से छूट प्रदान कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सीमा को 25-40 करोड़ रुपये तक ले जा सकती है। हालांकि स्टार्ट-अप कंपनियां एंजल टैक्स से पूरी तरह छूट चाहती हैं। एक सूत्र ने कहा, 'हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं। इनमें टैक्स छूट हासिल करने के लिए निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की भी जरूरत है।' गौरतलब है कि सैकड़ों स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल टैक्स के मद में बड़ी राशि चुकाने संबंधी नोटिस भेजे गए हैं। इसे लेकर स्टार्ट-अप कंपनियों में रोष है और सेक्टर सरकार से लगातार एंजल टैक्स खत्म करने की मांग कर रहा है।

टाटा ट्रस्ट्स ने लगाई आयकर छूट वापस लेने के खिलाफ अर्जी

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। टाटा ट्रस्ट्स की इकाई सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने आयकर विभाग द्वारा संस्था को आयकर से मिली छूट वापस लेने के एक फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई है। सूत्रों के मुताबिक मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमणन को ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मानदेय के मद में 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इसे बहुत बड़ी रकम मानते हुए आयकर विभाग ने टैक्स से मिली छूट पिछले वर्ष दिसंबर में वापस ले ली। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आयकर विभाग के इसी फैसले के खिलाफ अपील की गई है। हालांकि सूत्र ने यह नहीं बताया कि आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने का आधार क्या है। टाटा ट्रस्ट्स ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच, इस तरह की खबरें भी आई कि वेंकटरमणन ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर भी टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वेंकटरमणन इस्तीफा देने को तैयार थे।

आर.बी.आई. के नए नियमों से 1 मार्च से बंद हो सकते हैं आधे ए.टी.एम.

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के नए नियम ए.टी.एम. चलाने वाली कम्पनियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ए.टी.एम. चलाने की लागत बढने और आर.बी.आई. के नए नियमों के कारण ए.टी.एम. चलाने में कम्पनियों को कोई मार्जिन नहीं बच रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए कम्पनियां सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से ए.टी.एम. से लेन-देन पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की राय दे रहे हैं। कम्पनियों का दावा है कि अगर यह चार्ज नहीं बढ़ाया गया तो 1 मार्च से देश भर में आधे से ज्यादा ए.टी.एम. उन्हें बंद करने पड़ेंगे। इससे देश में एक बार फिर नोटबंदी जैसा हालात हो सकते हैं जब लोगों को कैश निकालने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। ज्यादातर सभी बैंक 80 से 90 फीसदी ए.टी.एम. सर्विस को आऊटसोर्स करते हैं। ए.टी.एम. की इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जुड़ी कम्पनी सिक्योरन्स सिस्टम के एम.डी. सुनील उडुपा ने बताया कि आर.बी.आई. के नए नियमों से ए.टी.एम. चलाने की लागत और बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि अभी वैन में कैश के साथ कैसेट्स भी जाते हैं। अगर एक वैन 10 ए.टी.एम्स के लिए कैश लेकर जाती है तो उसके पास इतनी जगह नहीं होती कि वह दोगुनी संख्या में कैसेट्स लेकर जाए। दूसरा, सामान्य गार्ड की तुलना में आर्म्ड गार्ड लेकर जाने से कॉस्ट दोगुनी हो जाती है क्योंकि उसका वेतन ज्यादा होता है। ए.टी.एम. कम्पनियों के मुताबिक मुंबई जैसी प्राइम लोकेशन में ए.टी.एम. साइट का किराया 40,000 रुपए पड़ता है। छोटे शहरों में भी ए.टी.एम. साइट का किराया 8,000 से 15,000 रुपए तक पड़ता है। इसमें सिक्योरिटी स्टाफ का वेतन, मैंटीनैंस चार्ज और बिजली खर्च मिलाकर ए.टी.एम. चलाना काफी महंगा पड़ रहा है। ए.टी.एम. की सुरक्षा एक बड़ी परेशानी भी बन रही है जिस पर बैंकों की तरफ से कोई खास काम नहीं किया जा रहा है। आर.बी.आई. ने ए.टी.एम. में लगने वाले कैसेट्स (जिनमें नोट रखे जाते हैं) की संख्या को डबल कर दिया है। कैश ले जाने वाले वैन में आर्म्ड गार्ड रखने के लिए कहा गया है। ए.टी.एम. में साइबर सिक्योरिटी को पहले से और पुख्ता करने के लिए कहा गया है।अभी देश में करीब 2.40 लाख ए.टी.एम. हैं और इनमें से 50 से 60 फीसदी ए.टी.एम. बंद हो सकते हैं क्योंकि इनको चलाने में घाटा हो रहा है।

पेट्रोल के दाम में मामूली गिरावट

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज पेट्रोल की कीमतों में 10 पैसे की कटौती की। हालांकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसकी कीमतें 7 फरवरी के स्तर पर बनी हुई हैं।राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 70.28 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे की कटौती हुई है और यह घटकर 72.39 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 75.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 72.95 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। डीजल की कीमतें दिल्ली 65.56, कोलकाता में 67.34, मुंबई में 68.65 और चेन्नई में 69.25 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई हैं।जानकारों की मानें तो मौजूदा समय में क्रूड ऑयल के दाम में कटौती देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में क्रूड के दाम में बदलाव दिखने के संकेत मिल रहे हैं।

छोटे किसानों के लिए कितनी बड़ी मदद है सालाना 6000

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। अंतिरम बजट में छोटे किसानों को 6 हजार रुपए की सालाना आर्थिक मदद देने के मोदी सरकार के ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के आंकड़ों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया है कि 6 हजार रुपए की सालाना मदद किसानों के लिए कितनी अहम है। पता चला है कि रकम छोटे किसानों की औसत सालाना आय का 6 प्रतिशत हिस्सा है। साल 2016 में एन.एस.एस.ओ. ने जुलाई, 2012 से जून, 2013 के बीच किसानों को होने वाली आय पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें औसत किसान परिवार को प्रति माह 6426 यानी सालाना 77,112 रुपए की कमाई होने की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम. किसान) की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा प्रिय नरेन्द्र मोदी जी 5 साल की आपकी अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्हें रोजाना 17 रुपए देने हर उस चीज का अपमान है जिसके लिए वे खड़े हैं और काम कर रहे हैं। पी.एम. मोदी भी विपक्ष को आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा-दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे लोग नहीं समझ सकते कि देश के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब किसानों के लिए 6 हजार रुपए क्या मायने रखते हैं।

निर्माणधीन फ्लैटों पर जीएसटी कम होने से मकान बिक्री रफ्तार पकड़ेगीः क्रेडाई

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने शुक्रवार को कहा कि यदि निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी कर की दरों को घटाकर तीन और पांच प्रतिशत किया जाता है तो मकानों की बिक्री रफ्तार पकड़ेगी। माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों का समूह कर दरें कम करने की सिफारिश कर सकता है। मंत्रियों का समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर इस कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में है।जीएसटी परिषद ने रियल एस्टेट क्षेत्र की दिक्कतों या चुनौतियों का पता लगाने और कर दरों की समीक्षा के पिछले महीने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समूह गठित किया गया था। समूह ने बैठक में किफायती आवास पर जीएसटी को 8 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का भी पक्ष लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेडाई के अध्यक्ष जैकसी शाह ने कहा कि यदि जीएसटी की दरों को घटा दिया जाता है तो लोग घर खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मौजूदा समय की जीएसटी अधिक होने की वजह से मकान खरीदने के फैसलों को फिलहाल के लिए टाल दिया है।

अब नहीं पड़ेगी टोकन और स्मार्ट कार्ड की जरूरत,यात्री बायोमीट्रिक से कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो में सफर

दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को टोकन और स्मार्टकार्ड की जरूरत पड़ती है। टोकन और स्मार्ट कार्ड बनाने की लाइन इतनी लंबी होती है कि यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों की इन्ही दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी तकनीक खोजी है जिससे यात्री बिना टोकन और स्मार्ट कार्ड के भी मेट्रो में आसानी से यात्रा कर पाएंगे। छ्वरूक्रष्ट किराया भुगतान को आसान बनाने के लिए सभी मेट्रो स्टोशनों पर बायोमेट्रिक आधिरित फेयर कलेक्शन गेट लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए सिर्फ फिंगर पंच करनी होगी।छ्वरूक्रष्ट ने अपनी इस बड़ी योजना की पुष्टि की है और इस बारे में अधिक जानकारी देने से इंकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना में 14.51 करोड़ की लागत से सभी मेट्रो स्टेशनों में बायोमेट्रिक आधारित फेयर कलेक्शन गेट लगाए जाएंगे। छ्वरूक्रष्ट ने इन फेयर कलेक्शन गेट लगाने के लिए एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। इन गेट्स पर अंगुलियों से पंच कर, टोकन और स्मार्ट कार्ड तीनों से किराया भुगतान की सुविधा होगी।मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो में 236 मेट्रो स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी बायोमीट्रिक सिस्टम से किराया भुगतान का नया विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालें 70 फीसद यात्री स्मार्ट कार्ड व 30 फीसद यात्री टोकन का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कई स्टेशनों पर टोकन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वैसे तो स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन रिचार्ज कराने की सुविधा है, फिर भी कई स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने में यात्रियों को 10 से 15 मिनट समय लग जाता है।

भारत लगातार चौथे वर्ष तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। भारत ने सबसे तेजी से बढ़ने वाले उड्डयन बाजार का रुतबा लगातार चौथे साल बरकरार रखा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) की ओर से जारी 2018 रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत के घरेलू बाजार ने लगातार चौथे वर्ष 18.6 फीसद की सबसे तेज वृद्धि दर हासिल की।'

आयटा के अनुसार, 'भारत के बाद उड्डयन में सर्वाधिक 11.7 फीसद की वृद्धि दर हासिल करने वाला देश चीन रहा है। दोनो ही देशों में घरेलू मांग बढ़ने की प्रमुख वजह सुदृढ़ आर्थिक विस्तार के अलावा युगल शहरों के बीच उड़ानों में बढ़ोतरी रही। खासकर भारत में लगातार 50वें महीने (अक्टूबर, 2018) में दो अंकों की वृद्धि दर देखने में आई। जबकि चीन में अर्थव्यवस्था के बढ़ते आधुनिकीकरण के चलते हाल के महीनों में कुछ सुस्ती के संकेत दिखाई दिए हैं।' नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार 2018 में 13.9 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्र की। यह संख्या 2017 के मुकाबले 18.6 फीसद अधिक है, जब 11.7 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्र की थी। इससे पहले 2017 में भारतीय घरेलू क्षेत्र में वृद्धि दर 17.3 फीसद, 2016 में 23.2 फीसद तथा 2015 में 20.3 फीसद रही थी। आयटा की रिपोर्ट बताती है कि 2017 और 2018 दोनो वर्षों में वैश्विक स्तर पर घरेलू हवाई सफर में औसतन सात फीसद का इजाफा हुआ था। इस दौरान भारत और चीन की अगुवाई में तकरीबन सभी बाजारों ने बढ़त हासिल की।भारत और चीन दोनो की वृद्धि दर दोहरे अंकों में रही। इस दौरान वैश्विक क्षमता में 6.8 फीसद तथा लोड फैक्टर में 83.0 फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह 2017 के मुकाबले 0.2 फीसद अधिक थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वर्ष भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे अर्थव्यवस्थाओं को भी मदद मिलेगी। वैश्विक बाजारों में पिछले छह महीनों के दौरान दिखी सुस्ती के लिए विशेषज्ञों ने ब्रेक्जिट तथा चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव तथा अनिश्चितता को जिम्मेदार ठहराया है।

एसबीआई ने 30 लाख रुपए तक को होम लोन किए सस्ते

मुंबइ, 09 फरवरी (ए)। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने घर खरीददारों को शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दी है। एसबीआई ने 30 लाख रुपए के होम लोन पर ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कटौती की है। स्टेट बैंक के इस निर्णय से कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। बैंक ने यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो रेट में कटौती के फैसले के एक दिन बाद लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया था, जिससे रेपो रेट 6.25 प्रतिशत हो गया है। रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद से ही ऐसी उम्मीद थी कि बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्टेट बैंक ने की। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही देश के अन्य बैंक भी ब्याज दरें घटा सकते हैं। निम्न और मध्यम आय वर्ग को होगा फायदा एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक के नाते हमने हमेशा ग्राहकों के हित को सबसे आगे रखा है। उन्होंने कहा कि होम लोन में एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऐसे में बैंक का यह निर्णय देश के उस बड़ी आबादी तक पहुंचेगा, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग से हैं।

मारुति से लकर फॉक्सवैगन तक लगी ऑफरों की झड़ी, मिल रहा भारी डिस्काउंट

नई दिल्ली, 09 फरवरी (ए)। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस साल की शुरूआत ही बंपर ऑफरों से हुई है। हालांकि बीता वर्ष ऑटोमोबाइल बाजार के लिए कुछ खास नहीं रहा लेकिन इस वर्ष के शुरूआत में ही वाहन निर्माताओं ने कई बेहतरीन मॉडलों को पेश किया है। इसके साथ ही कई कारों पर भारी डिस्काउंट और आकर्षण ऑफर भी मिल रहा है।भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों मे से एक मारुति सुजुकी ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के चलते मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप के जरिए बेचे जाने वाले सभी मॉडल्स पर 85 हजार रुपए तक की छूट दे रही है। Cia5 का पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए कंपनी इस मॉडल पर 60 हजार रुपए तक की छूट दे रही है। इसके साथ ही कंपनी ने ग्राहकों द्वारा पुरानी कार बेचे जाने पर भी ऑफर निकाला है। इस ऑफर के चलते यदि कोई ग्राहक अपनी पुरानी कार बेचता है तो उसे 25 हजार रुपए का बोनस दिया जाएगा। यह ऑफरU Cia5 की पेट्रोल और डीजल गाड़ी दोनों पर ही है। कपंनी ष्ट्वद्ब्ठ्ठ5 की ऑटोमैटिक कार पर 40 हजार रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। वहीं कंपनी ने 2019 MY Cia5 पर 10 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट रखा है। इसमें सिग्मा, डेल्टा और जेटा वर्जन शामिल है। साथ ही 25 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। बता दें कि इससे पहले कंपनी ने पुरानी वैगनआर पर 83 हजार रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया था क्योंकि वह हाल में लॉन्च न्यू WagonR की सेल बढ़ाना चाहती है। कंपनी ऑल्टो 800 पर 43000 रुपए तक डिस्काउंट ऑफर कर रही थी।दक्षिण कोरिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनी हुंडई अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार Hyundai Grand i10 के 2018 मॉडल पर पूरे 80,000 रुपए की छूट दे रही है। इस कार के पेट्रोल वैरिएंट में कंपनी 50,000 रुपए का कैशबैक और 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। वहीं Hyundai Grand i10 के डीजल वैरिएंट पर कंपनी 60 हजार रुपए का कैशबैक और 20 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। हुंडई की ये कार हैचबैक सेग्मेंट में काफी लोकप्रिय रही है।देश की प्रमुख एसयूवी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Mahindra KUV100 पर 73,000 रुपए का छूट दे रही है। जिसमें 40 हजार रुपए का कैशबैक, 29,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 4000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। यदि आप भी इस बेहतरीन एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शानदार मौका है।हुंडई की शानदार सिडान कार Hyundai Xcent पर भी भारी छूट मिल रही है। इस कार के 2018 मॉडल पर कंपनी 85,000 रुपए की छूट दे रही है। जिसमें 40,000 रुपए का कैशबैक और 45,000 रूपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है।